भारत पर सार्वजनिक ऋण का बोझ

डॉ0 संजय रस्तोगी

एम0कॉम0 पीएच.डी., विभाध्यक्ष वाणिज्य विभाग,
राजकीय संघटक महाविद्यालय पूरनपुर पीलीभीत, (उत्तर प्रदेश)

शोध सारांश

सार्वजनिक ऋण भारत सरकार द्वारा लिए गये समस्त उधारी को प्रदर्शित करता है इसके अन्तर्गत ट्रेजरीबिल, बाजारऋण रिजर्व बैंक द्वारा जारी विशेष ऋण प्रतिभूतियाँ यथा आंतरिक ऋण और बकाया वाह्याऋण शामिल है। तथा भविष्यनिधि छोटी बचते आरक्षित निधियाँ तथा जमाओं को इसके तहत नहीं शामिल किया जाता है। सरकार जीसेक और ट्रेजरी बिल नामक सरकारी प्रतिभूतियाँ को जारी करके उधार लेती है। देश के 14 प्रधानमंत्रियों ने मिलकर 67 वर्ष में कुल 55 लाख करोड़ रूपये का कर्ज लिया। पिछले 9 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने हिन्दुस्तान का कर्जा तिगुना कर दिया। 100 लाख करोड़ रूपयें से ज्यादा कर्ज उन्होंने मान 9 वर्षों में ले लिया है। एडम स्मिथ का कथन था कि "लोक ऋण से युद्ध एवं फिजूल खर्चों जैसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती है।

लोक ऋणों को महत्व

देश में अनेक ऐसें आर्थिक कारण उदय हो जाते है जिससे सरकार को कर के स्थान पर ऋण का सहारा लेना पड़ता है तथा जब सरकार को अपार मात्रा में धन की आवश्यकता हो तो एक साथ तुरन्त राशि प्राप्त होना सम्भव न होने से उसे ऋण पर ही निर्भर रहना पड़ता है भारत जैसे विकासशील देश विश्व बैंक एशिया बैंक व अन्य बैंकों पर ऋण के लिए निर्भर रहतें है। भारत में लोक ऋण व्यवस्था में अल्प बचतो का विशेष महत्व है। जो कि निर्धन वर्ग से प्राप्त होती है भारत की पंचवर्षीय योजनाओं में अल्प वचतो को विशेष महत्व दिया गया है। तथा वर्तमान में सरकार नौ प्रकार की छोटी वचत योजनाएँ देश में है जिसमें आवर्ती जमा (आर.डी.) सार्वजनिक भविष्यनिधि, सुकन्या समृद्धि योजना, महिला सम्मान वचत प्रमाण पत्र, किसान विकास पत्र, राष्ट्रीय वचत प्रमाण पत्र, एन एस सी तथा वरिष्ठ नागरिक वचत योजना, शामिल है। इस स्कीम में भारत ने सत्र 2022–23 में 3.04 लाख करोड़ रूपये प्राप्त हुए। जो सत्र 2021–22 की तुलना में 8ण्5ः कम था तथा सत्र 2021–22 में 3.33 लाख करोड़ रूपये थें। जो 11 वर्षों में पहली बार घटा है।

अन्तराष्ट्रीय मुद्रा कोष

भारत आई एम एफ का संस्थापक सदस्य देश है और इसका निर्माण करनें में भारत की बहुत ही अहम भूमिका रही थी। शुरू में भारत इस सस्था से सार्वजनिक ऋण लेता था पर सन् 1993 के बाद से भारत ने कोई वित्तीय सहायता नहीं ली और इस संस्था की पूरी ऋणों की अदायणी 31 मई 2000 को पूरी हो चुकी है।

अन्तराष्ट्रीय पुननिर्माण और विकास बैंक

विश्व बैंक के आई.बी.आर.डी. से सबसे अधिक ऋण लेनें वाला देश भारत है भारत ने 2015 से 2018 के बीच विश्व बैंक ने भारत को लगभग + 10ण्2 बिलियन का ऋण दिया है। विश्व बैंक समूह ने 2019–22 की अवधि में भारत के लिये 25–30 बिलियन डॉलर की योजनाओं को मंजूरी दी है। इसमें से भारत सरकार पर 161 लाख करोड़ रूपयें जबकि राज्य सरकारों पर 44 लाख करोड़ रूपये से ज्यादा कर्ज है 2014 में केन्द्र सरकार का कुल कर्ज 55 लाख करोड़ रूपये था जो सितम्बर 2023 तक बढ़कर 161 लाख करोड़ हो गया है।

एशियाई विकास बैंक

एशियाई विकास बैंक ने भारत को 2021 में रिकार्ड 4.6 अरब डॉलर का कर्ज दिया है इनमें से 1.8 अरब डॉलर का कर्ज कोरोना महामारी की वजह से पैदा हुई स्थिति से निपटनें के लिए दिया गया है। एशियाई विकास बैंक ने वीते साल यानी 2021 में भारत को रिकार्ड 4.6 अरब डॉलर का कर्ज दिया है।

भारत के हर नागरिक पर 30776 रूपये का विदेशी कर्ज

अगर हम लोग सार्वजनिक ऋणों को देखें तो भारत पर कुल 42.5 लाख करोड़ रूपयें का विदेशी कर्ज है। इस हिसाब से हर भारतीय करीब 30776 रूपये के कर्ज के नीचें दवा हुआ है जबकि कर्ज का सन् 2010 में करीब 21.9 लाख करोड़ रूपये का था। जो पिछलें 10 वर्षों में बढ़कर 96 फीसदी की वृद्धि के साथ बढ़कर सन् 2010 में 42.5 लाख करोड़ पर पहुँच गया है इसमें से 84.254 करोड़ रूपये का तो केवन ब्याज है जैसे लम्बी अवधि के दौरान चुकाया जाना है।

निष्कर्ष

सार्वजनिक ऋण सदा लाभकारी नहीं होता, इसका अत्यधिक प्रयोग अर्थव्यवस्था में मौद्विक संकट उत्पन्न कर देता है तथा सार्वजनिक ऋण युद्ध छोड़ने को उत्साहित करता है। इसलिए सार्वजनिक ऋण को वित्त व्यवस्था के लिए जोखिम पूर्ण माना जाता है यह एक सरल कार्य नहीं है बल्कि सार्वजनिक वित्त का प्रबन्ध तथा सम्भाल ध्यानपूर्वक तथा कार्य कुशलता से करने वाला कार्य है। **प्रो0 फिण्डलें शिराज** का मत है कि सरकार के लिए यह समझ लेना आवश्यक है उधार लेना समृद्धि की प्राप्ति के लिए सरल मार्ग नहीं है तथा ऋण सम्बन्धी नीति सीमित होनी चाहिए तथा ऋण केवल किसी उत्पादन व्यय के लिए लेना उचित है।

संदर्भ सूची

1. अमर उजाला
2. हिन्दुस्तान
3. दैनिक जागरण
4. प्रतियोगिता दर्पण
5. लोक वित्त – डॉ0 जे.सी. वाष्णैंय
6. लोक वित्त – डॉ0 पी.के. अग्रवाल
7. भारत की राजव्यवस्था – एम. लक्ष्मीकान्त
8. लोक वित्त – डॉ0 ए.के. पाण्डेय
9. लोक वित्त – डॉ0 एस.एम. नेगी
10. लोक वित्त – डॉ0 एस. दीक्षित
11. लोक वित्त – डॉ0 एम.एल. यादव
12. https: \\ www. drishtiias. com
13. https: \\ m. economics times. com
14. https: \\ www. bhaskar news. com
15. https: \\ dea. gov.in India IMF
16. https: \\ www. bhaskar. com